



प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

25 फरवरी / February , 2021

**राज्य में एमएसएमई पारितंत्र के विकास हेतु सिडबी ने
आंध्र प्रदेश सरकार के साथ गठबंध किया**

**SIDBI joins hands with Government of Andhra Pradesh for the Development
of MSME ecosystem in the State**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, ने राज्य में एमएसएमई पारितंत्र को विकसित करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया है। यह समझौता ज्ञापन, आंध्रप्रदेश सरकार के कैबिनेट उद्योग मंत्री श्री मेकापति गौतम रेड्डी की उपस्थिति में, श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम, आईएएस, उद्योग निदेशक, वाणिज्य और निर्यात संवर्द्धन, आंध्रप्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), हैदराबाद के क्षेत्रीय प्रमुख श्री संजय जैन, महाप्रबंधक के द्वारा निष्पादित किया गया।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing, and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Andhra Pradesh to develop the MSME ecosystem in the State. The MoU was signed by Shri J.V.N. Subramanyam IAS, Director of Industries, Commerce and Export Promotion, Government of Andhra Pradesh and Shri Sanjay Jain, General Manager, Regional Head, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Hyderabad, in the presence of Shri Mekapati Goutham Reddy, Cabinet Minister of Industries, Govt. of Andhra Pradesh.

इस समझौते के तहत सिडबी द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार के साथ एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) तैनात की जाएगी। पीएमयू की भूमिका इक्विटी समर्थन, ब्याज सबवेंशन, दबावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के समाधान, एमएसएमई उद्यमियों को सहयोग करने और एमएसएमई इकाइयों की मौजूदा स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर अन्य आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप को सुसाध्य बनाने की होगी। यह पीएमयू; वर्तमान में चल रही योजनाओं, हस्तक्षेपों, पहलों, परियोजनाओं आदि, जो वर्तमान में राज्य के एमएसएमई उद्यमों की ओर लक्षित / उनके लाभ के लिए उपलब्ध हैं, के मौजूदा ढांचे का अध्ययन

करेगी और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने तथा बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधनों के बारे में सुझाव देगी।

Under the agreement, a Project Management Unit (PMU) will be deployed by SIDBI with Government of Andhra Pradesh. The role of the PMU will be to design schemes/programmes in the areas of equity support, interest subvention, resolution of stressed MSMEs, supporting MSME entrepreneurs and facilitate other need-based intervention based on evaluation of the existing status of MSMEs. The PMU will study existing framework of schemes, interventions, initiatives, projects etc. which are currently available for the benefit of / targeted towards MSMEs in the State and shall suggest modifications, if any, with the objective of enhancing efficacy and removal of bottlenecks.

इस अवसर पर, सिडबी के उप-प्रबंध निदेशक श्री वी. सत्य वेंकटा राव ने कहा, “राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारे सुनियोजित दृष्टिकोण को लेकर, हमने कई राज्यों के साथ क्लस्टर पहुँच कार्यक्रमों को शुरू किया है। हमने आत्मनिर्भर भारत की तैयारी के रूप में विभिन्न राज्यों में क्लस्टर विकास के आधारभूत ढाँचे विषयक पहलुओं का समर्थन करने के लिए एक क्लस्टर विकास निधि का भी प्रस्ताव किया है। अब तक 10 राज्यों में की गई पीएमयू की स्थापना के लक्ष्यानुसार सुदृढ़ एमएसएमई पारितंत्र के लिए ऋण-प्रदायगी के विभिन्न अग्रणी प्रकारों के साथ सघनता से जुड़ाव के लिए विशेषज्ञों की बाह्य टीम के नियोजन पर हमारा ध्यान केन्द्रित है। हमारे इस गठबंधन का लक्ष्य अच्छी प्रथाओं का पालन करना, मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों को फिर से जीवंत करना और अधिक संवेदनशील पारितंत्र को सक्षम बनाना होगा।”

On this occasion, Shri V. Satya Venkata Rao, Deputy Managing Director of SIDBI said, “In line with our programmatic approach to foster closer cooperation with the State Government, we have started with cluster outreach programs with several States. We have also proposed a cluster development fund for supporting the infrastructural aspects of cluster development in various States as preparation for AatmaNirbhar Bharat. The setting up of PMUs in 10 States so far is targeted at placing expert outsourced team for more focused engagement in various forms leading to a stronger MSME ecosystem. Imbibing good practices, rejuvenating existing programs and policies, and enable more responsive ecosystem shall be the target of our joining of hands.”

10 राज्यों में पहले से ही मौजूद परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) ने एमएसएमई क्षेत्र के लाभार्थियों को लक्षित करने वाली केंद्रीय और राज्य विशिष्ट योजनाओं का संकलन-कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। पीएमयू इन राज्यों की मौजूदा औद्योगिक नीतियों का विश्लेषण भी कर रहा है ताकि अन्य नीतिगत स्तर के सुझावों और हस्तक्षेपों के अलावा सुझाव भी दिए जा सकें।

The PMUs already in place in 10 states have already completed the compilation of Central and State specific schemes targeting MSME sector beneficiaries. The PMU is also carrying out analysis of existing industrial policies of these states to offer suggestions apart from other policy level suggestions and interventions.

यह विकासात्मक पहल, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एमएसएमई उद्यमों पर गठित यू.के. सिन्हा समिति की रिपोर्ट में दर्ज अपेक्षाओं से जुड़ी है। इससे एमएसएमई के संवर्द्धन और विकास के

लिए राज्य सरकारों के साथ सिडबी की संकेंद्रित संलग्नता और बढ़ेगी। पीएमयू, राज्य में एमएसएमई उद्यमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे - पीएसबीलोनसइन59मिनिट्स, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि पर खुद की ऑनबोर्डिंग के लिए पथ-प्रदर्शन करने की प्रक्रिया भी तैयार करेगा। इसके अलावा पीएमयू, राज्य के भीतर और बाहर दोनों स्थलों की अच्छी प्रथाओं और दिशानिर्देशों की मैपिंग कर भंडार बनाने में भी संलग्न होगा और राज्य में अच्छी प्रथाओं को अपनाए जाने को सुसाध्य बनाएगा। यह एमएसएमई के हितार्थ किए जा रहे हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा और नीतिगत अनुसमर्थन के लिए निविष्टियाँ भी प्रदान करेगा।

This development initiative is aligned to expectations laid down in UK Sinha Committee on MSMEs set up by RBI. It envisions more focused engagement of SIDBI with State Governments for MSME promotion & development. The PMU will also prepare the process for handholding MSMEs in the State for their onboarding onto digital platforms such as PSBLoansIn59Minutes, Stock Exchange listing, e-commerce platforms such as Government e-Marketplace etc. Along with that, the PMU will also engage in mapping repository of good practices and guidelines both within and outside the State and facilitate adoption of good practices. It will create a framework for evaluating impact of interventions being made for the benefit of MSMEs and shall also provide inputs for policy advocacy.

सिडबी के बारे में : 1990 में अपने गठन के बाद से, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चाहे वे पारंपरिक, छोटे घरेलू उद्यमी हों, पिरामिड के सबसे निचले स्तर के उद्यमी हों, या फिर उच्च-स्तरीय ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को विभिन्न ऋणों तथा विकास कार्यों के माध्यम से प्रभावित किया है। सिडबी 2.0 अपने साथ समावेशी, अभिनव और प्रभाव-उन्मुख संलग्नकता की दृष्टि को लेकर चल रहा है।

अधिक जानकारी के लिए <https://www.sidbi.in> पर जाएँ।

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements. SIDBI 2.0 carries the vision of inclusive, innovative and impact-oriented engagements.

To know more, check out: <https://www.sidbi.in>

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई मेल: neelasrib@sidbi.in

Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in